IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार के गरीबी उन्मूलन में नाबार्ड की भूमिका

संजीव कुमार प्रभाकर (वाणिज्य)
पिता– महेश प्रसाद
ग्राम– बुन्देलखण्ड
पो0 बासोपट्टी
जिला– मधुबनी (बिहार)

गरीबी से तात्पर्य मानव की आधारभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ती न हो पाना अर्थात गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या सुमुदाय के पास अपने जीवन स्तर के न्यूनतम आवश्यक धन का आभाव होना । दूसरे शब्दो में कहा जा सकता है कि गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें समाज का एक भाग सही ढंग से अपनी न्यूनतम आवश्यकता यथा–रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ती नही कर पाता है। गरीबी के लिए उपभोग एवं आय का आधार माना जाता है। सही ढंग से गरीबी या निर्धनता को समझने के लिए व्यक्ति के सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्टभूमि का समझना आवश्यक है। सामान्यतः आर्थिक दृष्टिकाण से समाज के लोगो को चार अवस्थाओं में बाँटा जाता है। प्रथम वे होते है जिनका निर्वाह स्तर न्यूनतम होता है। दूसरा वे लोग होते है जो आसानी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है तिसरा वे लोग होते है जो आराम से जीवन व्यतीत करते है। तथा चौथा वे लोग होते हे जो बिलासता के स्तर के रूप में होते है।

आयामः–

1.) पर्याप्त भोजन का आभावः–
2.) समुचित आवास का अभावः–
3.)स्वास्थ्य का निम्न स्तरः–
4.) शिक्षा का निम्न स्तरः–
5.) स्वच्छ जल का आभावः–
6.) उचित परिधानो का आभावः–

प्रकारः– गरीबी अथवा निर्धनता को दो श्रेणी में बाँटा गया है

1.) पूर्ण निर्धनता / गरीबी यह निर्धनता की ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं यानि रोटी, कपड़ा एवं मकान की भी पूर्ती नही कर पाता है।

2.) सापेक्ष गरीबीः– गरीबी की ऐसी अवस्था है जिसमें सामाजिक परिपक्ष्य में परिवेश में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानको की तुलना में जीवन स्तर होता है।

जहाँतक गरीबी के आकलन की बात है तो इनका आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा संग्रह किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना की जाती है। इसके लिए उपभोक्ता व्यय का आधार माना जाता है। एवं गरीबी की घटना को गरीबी अनुपात द्वारा मापा जाता है जिसे प्रतिशत के रूप

में व्यक्त किया जाता है। इस संबंध में अलघ समिति (1979) ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एक व्यस्क के लिए क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण की बात कही। लकड़ावाला समिति 1993 एवं तेंदूलकर समिति 2009 एवं रंगराजन समिति 2012 ने अपने–अपने स्तर से गरीबी आकलन के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया।

जहाँतक रंगराजन समिति की रिपोर्ट की बात है तो इन्होने वर्ष 2014 में गरीबी रेखा का अनुमान मासिक प्रति व्यक्ति रूपयें का व्यय है। शहरी क्षेत्र में 1407 और ग्रामीण क्षेत्र 972 रूपये रखा।

गरीबी का जाल

च्तवअमतजल ज्तंच

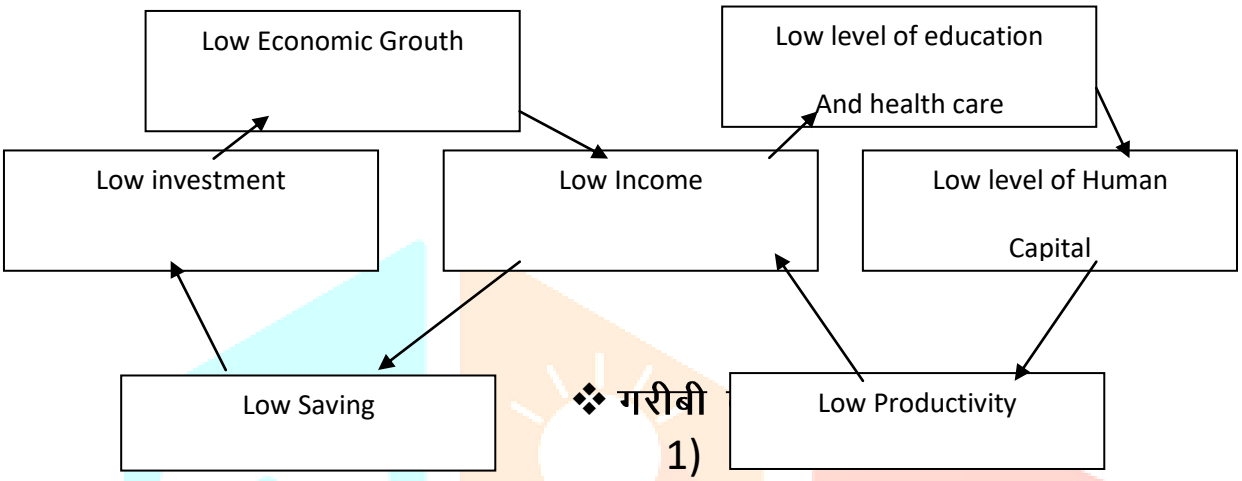

❖ गरीबी

1)

2) कम कृषि उत्पादकताः–

3) आर्थिक विकास की दर निम्नः–

4) मूल्य वृद्धिः–

5) बेरोजगारीः–

6) अशिक्षाः–

7) पूँजी एवं उधमशीलता की कमीः–

8) सामाजिक कारण (जाति प्रथा):–

9) जलवायु कारक (बाढ, आपदा, भूकम्प, चक्रवात आदि):–

❖ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमः–

गरीबीउन्मूलन कार्यक्रम से पहले गरीबी उन्मूलन के अर्थो को समझना बेहद जरूरी है गरीबी उन्मूलन से तात्पर्य गरीबी से निजात पाना अर्थात गरीबी को बिल्कुल खत्म करना। इस गरीबी को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाये जा रहें है उसे ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

- जवाहर रोजगार योजना
- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- इंदिरा आवास योजना
- काम के बदले अनाज योजना
- राष्ट्रीय बृद्धावस्था पेंशन योजना
- अन्नपूर्णा योजना (1999–2000)
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामोण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005)

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011)
- जन–धन योजना
- कौशल विकास योजना

❖ बिहार के परिप्रेक्ष्य में गरीबी:–

बिहार के संदर्भ में गरीबी की बात जहाँ तक है तो यहाँ की कुल आवादी का लगभग 33.07 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी रेखा से निचे जीवन बसर कर रहे है अन्य राज्यों से इसकी तुलना को जाए तो झारखंड में 37%, पश्चिम बंगाल में 20% एवं अरूणाचल प्रदेश में 34.07% है। देश के 640 जिलो में से वैसे जिले जहाँ 60% गरीब है ऐसे जिलो की आवादी लगभग 4 करोड़ है इन 4 करोड़ लोगो में से लगभग 2 करोड़ 80 हजार लोग बिहार के इन्ही 11 जिलो में रहते है ये जिला है उतरी बिहार के मधेपुरा अररिया मधुबनी, सुपौल, आदि है। करीब 1 करोड़ 60 हजार उत्तर प्रदेश में तो शेष छतीसगढ, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में रहतें है। वैसे तो 2005–06 से 2015–16 के बीच गरीबो की संख्या में 50: की गिरावट हुई है देश में अभी भी 36.4 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ईडेक्स के दायरे में है जो पश्चिमी यूरोपीय देशों यथा–जर्मनी, फ्रांस, U.K स्पेन, पूर्तगाल, इटली, नीदरलैण्ड,बोल्जियम की कुल आवादी से अधिक है। कृषि मंत्रालय और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट " Agricultural Statistics at a Glance 2017" के अनुसार वर्ष 2004–05 में बिहार में 54.4% परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे है इसमें 55.7% प्रतिशत आवादी ग्रामीण क्षेत्र में और 43.7% प्रतिशत शहरी क्षेत्र में। वर्ष 2009–10 मे BPL परिवारो की संख्या घटकर 53.5% रह गई इसमें 55.7% ग्रामीण एवं 43.7% शहरी आवादी थी। वर्ष 2004–05 और 2009–10 के दौरान बिहार के गॉवो में रहने वाले गरीबों की आवादी 0.9% घटी एवं शहरो में गरीबों की संख्या 4.3% घटी। वर्ष 2009–10 में शहरो में 55.3% BPL परिवार रह गए जबकि गॉवो में 39.4% गरीब रह गये।

वर्ष 2009–10 और 2011–12 के बीच BPL परिवारो की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई इस दौरान मात्र तीन साल में बिहार ने 19.8% आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। संयुक्त राष्ट्र संध आर से जारी वैशिक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (GMDPI-MPI) ग्लोबल मल्टी–डाइमेंशनल पॉवर्टी इडेक्स– MPI के ताजा रिपोर्ट में बतलाया गया है कि बिहार के MPI में 50% की सुधार हुआ है। फिर भी बिहार की गिनती सबसे गरीब राज्य में होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर क तीन मानको के 10 संकेतको पर आधारित है। रिपोर्ट भी चौकाता है कि बिहार के 38 जिलों में से 11 ऐसे जिले है जिसमें 10 मे स 06 लोग गरीब है। यह जिला मुख्यतया उत्तर बिहार में है। अररिया व मधेपुरा में गरीबो की यह संख्या बढकर 10 में 7 हो जाती है।

गरीबी उन्मूलन में नाबार्ड की भूमिका:–

जैसा कि हम सभी जानते है कि नावार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) की स्थापा 12 जूलाई 1982 को किया गया। यह शिर्ष वित्त संस्था है। 100 करोड़ अधिकृत पूजी से शुरू हुई यह वर्तमान में 3000 करोड़ पूँजी तक पहूँच गई है। यह भारत के विभन्न राज्यों की राजधानी समेत देश के लगभग 340 जिलो में अपने क्षेत्रीय कार्यालय एवं लगभग 3000 से अधिक कर्मचारियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के कृषि बेरोजगारी, गरीबी एवं दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था कर उनके चौमुखी उन्नति में अपनी भूमिका अदा कर रही है।

जहाँतक गरीबी उन्मूलन में नावार्ड की भूमिका की बात है तो यह सरकार के साथ मिलकर कई विकास कार्यक्रम चला रहा है। पहले चरण में जहाँ 213 गॉवो में यह पुरा हो चुका है वही दूसरे चरण मे भी कई गॉवों को शामील किया गया है।

कृषक उत्पाद को नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 65 नए उत्पादक संगठनो के लिए 157.72 करोड़ रूपयें की वित्तीय सहायता मंजूर की है। नाबार्ड बास प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना डेयरी गतिविधियाँ, माहिलाओ के स्वयं सहायता समूह हेतू वित्त पोषण, तल मिलो, आँटा मिलो, कृषि सेवा केन्द्रो, कृषि, बागवानी, विपणन की बुनियादी सुविधाएँ का निर्माण शामिल है।

नाबार्ड गरीबी उन्मूलन हेतू विपणन महासंघो, निगमो और सहकारी संस्थाओं के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है।

नाबार्ड कृषि संवर्धन निति के तहत वर्ष 2014–15 के तहत 4165 (एफ सी) मंजूर किए गए जिन्हे मिलाकर क्लबो की संख्या 1.47 लाख हो गया है।

कृषक क्लबों को 54,700 मोबाईल फोन देने की पहल की गई है। नाबार्ड ने लगभग 729 किसानो को मास्टर किसानो के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए राज्यो में कई परियोजना के लिए अनुदान सहायता वितरित की है।

नाबार्ड द्वारा पुनर्वित पोषण (करोड़ सं0)

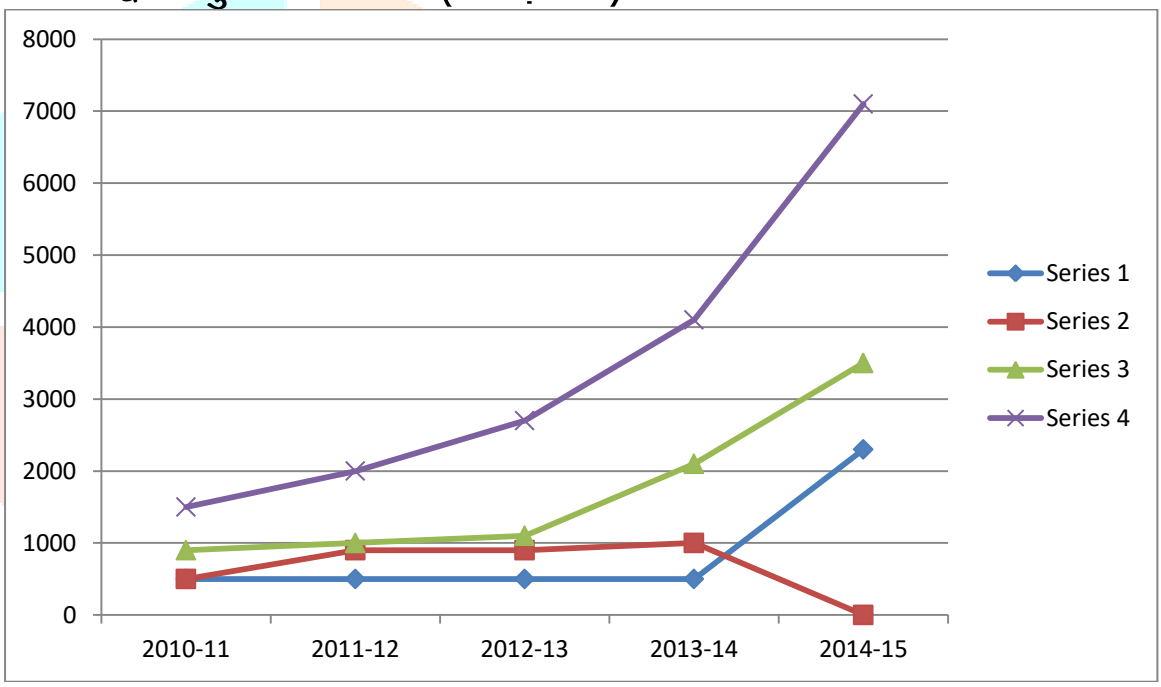

(स्त्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 वित्त विभाग बिहार सरकार पटना, फरवरी पृष्ट 281)

नाबार्ड द्वारा बिहार में विभिन्न क्षेत्रो में निवेश ऋण पुनर्वित की जो व्यवस्था करती है उसे आरेख के द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जा रहा है।

क्षेत्र	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
लधु सिचाई	39.38	32.72	46.57	17.89	25.25
कृषि यंत्रीकरण	81.92	97.76	250.84	67.27	295.60
दुग्ध शाला	92.56	70.62		31.11	104.59
स्वयं सहायता समूह	40.57	43.66		63.38	114.24
गैर–कृषि क्षेत्र	22.84	97.80	53.56	21.26	298.06
अन्य	8.72	33.98	170.46	169.73	1319.30
योग	285.99	376.54	521.43	370.64	2157.36

(स्त्रोत नाबार्ड की वेवसाइट)

नाबार्ड स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बिहार में गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है नावार्ड ने राज्य के हर जिले में एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन को आधार बनाकर महिला स्वयं सहायता समूह को बढावा देने और उनका वितपोषण करने के लिहाज से राज्य में 16 जिलो की पहचान की है।

सूचक	मार्च 2014	मार्च 2015
आच्छादित ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूह (लाख)	32.4	29.18
बैंक में बचत खाता वाल S.H.G की संख्या	2.69	2.24
बिहार में प्रति S.H.G और बचत (संख्या)	6127.0	13216
भारत में प्रति S.H.G और बचत (संख्या)	13321.0	14368
बैंक ऋण पाने वाले स्वयं सहायता समूह की सं0	190171	189341
वकाया बैंक ऋण राशि (लाख)	89814.2	102675.69
वर्ष के दौरान बैंक ऋण पाने वाले S.H.G की सं0	40036	65122
बैंक ऋण राशि (लाख रू0)	28400.00	47100.54
बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह और बैंक ऋण	0.70	0.72
भारत में स्वयं सहायता समूह और बैंक ऋण	1.75	1.69
सकल अनिष्पादित परिसंपति (लाख रू0)	7057.6	7130.35
बिहार में कुल वकाया ऋण में अनिस्पादित परिसंपतिको का प्रतिशत	7.86	6.94

(स्त्रोत नाबार्ड की वेबसाइट)

बैंको ने 2014–15 में राज्य के अतिरिक्त 51,403 स्वयं सहायता समूहो को ऋण–संपर्क उपलब्ध कराया है इस मामले मं प्रदर्शन 2013–14 से सुधरा है। जब 41,714 स्वयं समूहो को बैंक के साथ समबध किया गया था।

बिहार में सूक्ष्म–वित्तपोषण का विकास

वर्ष	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
वर्ष में नए ऋण सपर्कित समूहो की सं0	30241	26055	22714	30297	41714	51403

निष्कर्षः–

उपरोक्त सभी पहलूओं के अध्ययन के उपरांत कहा जा सकता है कि नाबार्ड सस्थागत विकास, नवाचारी प्रयास, रोजगार के अवसरो का सृजन, ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण मार्ट एवं हाट, छोटे शिल्पकारों,स्वयं सहायता समूहो, विपणन के संवर्धनों आदि में पुनवित ऋण एवं अनुदान संबंधी सहायता प्रदान कर बिहार के गरीबी उन्मूलन में सार्थक भूमिका निभा रहा है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर नावार्ड ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए शहरी क्षेत्र से धन जुटाता है।

जिसका परिणाम यह हुआ है। कि गाँव में निवास करने वाले व्यक्ति, किसान, उद्यमी एवं समूह से जुड़े महिलाओं आदि आत्मनिर्भरता की ओर बढ रहा है। इससे व्यक्ति के जीवन यापन, रहन–सहन उच्च स्तर की ओर अग्रसर हो रहा है परिणामस्वरूप बिहार में गरीबी की संख्या उतरोतर घटती जा रही है।

सन्दर्भ ग्रंथः–

1) सिंह, नरेन्द्रपाल और सिंह, लोकेन्द्र (2015) गॉवो के विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका, करूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 10, अगस्त, पृष्ट 32
2) WWW.nabard.org.
3) नावार्ड वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15
4) संयुक्त राष्ट्र अंतरष्टोय श्रम संगठन की वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक दृष्ट्रिकोण पर जारी रिपोर्ट 2017 हिन्दुस्तान, 14 जनवरी 2017 पटना संस्करण पृष्ट 12 से उदधृत
5) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार के आकड़े।
6) वार्षिक प्रतिवेदन 2015 नाबार्ड
7) आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16
8) सुदरम्, जोमो क वामे एवं चौधरी अनीस (2013) विकास, रोजगार एवं गरीबी, योजना, वर्ष 58, अंक 10, अक्टूबर, पृष्ट 34
9) स्टेट स ऑफ माइक्रोफाइनांस इन इण्डिया 2014–15